राज एक्सप्रेस, भोपाल 20 AUG 2011

अब सर्वे आफ इंडिया के नक्शों में प्रदेश में बनीं सड़कें

मप्र देश में पहला ऐसा राज्य बना

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों को सर्वे आफ इंडिया के नक्शों में शामिल किया गया है। इस तरह की उपलब्धि देश में पहली बार मप्र को मिली है। इससे देश विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति को नक्शों के जरिए प्रदेश की सड़कों का अंदाजा लग जाएगा। इस नक्शे में प्रदेश की नौ जिलों की सड़कों को स्थान मिला है।

मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के साधिकार समिति की बैठक मंत्रालय में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अवनि वैश्य ने की। बैठक में जाकनारी दी गई कि प्रदेश की नौ जिलों की सड़कों के निर्माण के लिए समेकित कार्य योजना से राशि मिलेगी। इन सड़कों को सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में दर्शाने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अरुणा शर्मा, मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय दुबे ने जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त जीपी सिंघल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण केके सिंह, प्रमुख सचिव वन स्वदीप सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अजय तिर्की एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इन जिलों की सड़कें हैं शामिल

समेकित कार्य योजना के तहत प्रदेश के 9 जिलों बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली और सिवनी में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा समेकित कार्य-योजना में 250 से 499 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिये 614.61 करोड़ प्रदान करने की सहमति दी गई है। राज्य सरकार 2.83 करोड़ की राशि खर्च करेगी।

1210 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति

मप्र की 2069 किमी सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें समेकित कार्य-योजना के जिलों को कम कर उनके स्थान पर न्यूनतम कार्यभार के जिलों को जोड़कर 22 जिलों के 2140.39 किलोमीटर लम्बाई केलिए 787.36 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए।